



Garvi Gujarat

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15

अंक : 307

दि. 11.03.2026,

बुधवार

पाना : 04

किंमत : 00.50 पैसा

डिजिटल निगरानी के साथ गांव-गांव तक नल से जल पहुंचाने का नया संकल्प

जीएनएस)। नई दिल्ली। ग्रामीण भारत में सुरक्षित और नियमित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी जल योजना को नए चरण में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में Jal Jeevan Mission के दूसरे चरण को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के साथ मिशन को अक्टूबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है और इसके लिए लगभग 8.69 लाख करोड़ रुपये का विशाल बजट तय किया गया है। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा करीब 3.59 लाख करोड़ रुपये होगा, जबकि शेष राशि राज्यों और अन्य स्रोतों के माध्यम से जुटाई जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि तय समय सीमा तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घर तक नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए और इस पूरी व्यवस्था को तकनीकी और डिजिटल निगरानी से जोड़ा जाए, ताकि पारदर्शिता और गुणवत्ता दोनों सुनिश्चित की जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या लंबे समय से

सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से जुड़ी रही है। खासकर महिलाओं और बच्चों को रोजाना कई किलोमीटर दूर से पानी लाने की मजबूरी का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या को दूर करने के लिए वर्ष 2019 में इस राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई थी। उस समय देश के ग्रामीण इलाकों में केवल लगभग 3.23 करोड़ परिवारों यानी करीब 17 प्रतिशत घरों तक ही नल से पानी पहुंचता था। पिछले कुछ वर्षों में इस मिशन के तहत तेजी से काम किया गया और आज यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 15.80 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहुंच गया है, जो कुल ग्रामीण घरों का करीब 81.61 प्रतिशत है। सरकार अब इस उपलब्धि को पूर्ण कवरेज में बदलना चाहती है और इसके लिए मिशन 2.0 को व्यापक स्वरूप दिया गया है। मिशन के नए चरण की सबसे खास बात यह है कि अब केवल पाइपलाइन और जल स्रोतों के निर्माण पर ध्यान नहीं रहेगा, बल्कि सेवा वितरण और प्रबंधन प्रणाली को भी मजबूत बनाया जाएगा। इसके लिए पूरे देश में एक समान डिजिटल ढांचा विकसित किया जाएगा



जिसे "सुजलम भारत" प्रणाली के रूप में लागू किया जाएगा। इस प्रणाली के तहत हर गांव को एक विशिष्ट "सुजल गांव आईडी" दी जाएगी। इस डिजिटल पहचान के माध्यम से गांव में मौजूद जल स्रोत, जलाशय, पाइपलाइन, ट्रीटमेंट प्लांट और घरों तक पहुंचने वाले कनेक्शन तक की पूरी व्यवस्था को डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा। इससे पानी की आपूर्ति, गुणवत्ता और रखरखाव पर निगरानी रखना आसान होगा और किसी

भी समस्या की जानकारी तुरंत मिल सकेगी। डिजिटल निगरानी प्रणाली का उद्देश्य यह भी है कि जल आपूर्ति व्यवस्था अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बने। जब किसी गांव की जल प्रणाली का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से दर्ज होगा तो प्रशासन को यह समझने में आसानी होगी कि पानी का स्रोत क्या है, उसकी क्षमता कितनी है, वितरण कैसे हो रहा है और किन स्थानों पर सुधार की जरूरत है। इससे पानी के दुरुपयोग या अनियमित आपूर्ति जैसी समस्याओं को भी कम करने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि तकनीक के इस्तेमाल से ग्रामीण जल प्रबंधन में नई दक्षता आएगी और योजना की सफलता लंबे समय तक बनी रह सकेगी। इस मिशन में ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण मानी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जल आपूर्ति प्रणाली केवल सरकारी परियोजना बनकर न रह जाए, बल्कि गांव के लोग भी इसके संचालन और रखरखाव में भागीदारी निभाएं। इसी उद्देश्य से "जल अर्पण" प्रक्रिया को लागू किया जाएगा, जिसके तहत ग्राम पंचायतें और

ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियां सक्रिय रूप से योजना के संचालन में शामिल होंगी। कोई भी गांव तभी "हर घर जल" प्रमाणित घोषित किया जा सकेगा जब राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर लेगी कि यहां पानी की आपूर्ति की व्यवस्था स्थायी है और उसका रखरखाव सही तरीके से किया जा रहा है। समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए हर साल "जल उत्सव" जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों के माध्यम से ग्रामीणों को जल संरक्षण, स्वच्छता और जल प्रबंधन के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। सरकार का मानना है कि यदि लोग पानी के महत्व को समझेंगे और उसका संरक्षण करेंगे, तभी ऐसी बड़ी योजनाओं का दीर्घकालिक लाभ मिल सकेगा। मिशन के सामाजिक प्रभावों को लेकर भी कई सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। सरकारी आंकड़ों और विभिन्न संस्थानों की रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना ने ग्रामीण जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। State Bank of India की रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि इस मिशन के कारण लगभग 9 करोड़ महिलाओं

को रोजाना पानी लाने की कठिन मेहनत से राहत मिली है। इससे महिलाओं के समय और ऊर्जा की बचत हुई है, जिसे वे अब शिक्षा, रोजगार या परिवार के अन्य कार्यों में लगा पा रही हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इसके महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं। World Health Organization के अनुसार, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने से डायरिया जैसी जलजनित बीमारियों से होने वाली लगभग 4 लाख मौतों को रोकने में मदद मिली है। सुरक्षित पानी मिलने से बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर पड़ा है। आर्थिक दृष्टि से भी यह मिशन रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायक साबित हुआ है। Indian Institute of Management Bangalore और International Labour Organization के संयुक्त आकलन के अनुसार, इस योजना के माध्यम से लगभग 59.9 लाख प्रत्यक्ष और करीब 2.2 करोड़ अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। पाइपलाइन निर्माण, जल ट्रीटमेंट संयंत्र, रखरखाव सेवाओं और स्थानीय स्तर पर

प्रबंधन कार्यों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति दी है। विकास अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता Michael Kremer ने भी इस योजना के संभावित दीर्घकालिक प्रभावों का उल्लेख किया है। उनके आकलन के अनुसार, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता बढ़ने से पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में लगभग 30 प्रतिशत तक कमी आने की संभावना है। यह संकेत देता है कि पानी की उपलब्धता केवल बुनियादी सुविधा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और सामाजिक विकास का भी आधार है। कैबिनेट बैठक में जल जीवन मिशन के विस्तार के साथ-साथ कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। सरकार ने Madurai Airport को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने को मंजूरी दी है। इस निर्णय से तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों में व्यापार, पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा यात्रियों की संख्या में वृद्धि और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की संभावना भी बताई जा रही है।

लोकसभा में तीखी नोकझोंक: प्रियंका और रिजीजू के बीच तंज और जवाब का दिलचस्प मुकाबला

जीएनएस)। नई दिल्ली। संसद के भीतर कभी-कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब राजनीतिक बहस केवल औपचारिक चर्चा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि नेताओं के बीच तीखे लेकिन रोचक संवाद का रूप ले लेती हैं। लोकसभा में उस समय ऐसा ही दृश्य देखने को मिला जब अध्यक्ष पद से Om Birla को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijju और कांग्रेस सांसद Priyanka Gandhi Vadra के बीच तीखी लेकिन शिष्टाचारपूर्ण जुबानी टकराव हुआ। सदन में हुई इस बहस में तंज, मुस्कान और फलटवार का ऐसा क्रम चला जिसने पूरे माहौल को कुछ देर के लिए राजनीतिक नाटक जैसा बना दिया। चर्चा के दौरान जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजजू ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने विपक्ष के प्रदर्शन और खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi के रवैये पर सवाल उठाए। अपने वक्तव्य में उन्होंने हल्के व्यंग्य के साथ कहा कि यदि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया होता तो शायद विपक्ष का प्रदर्शन अधिक प्रभावी और गंभीर दिखाई देता। उन्होंने यह भी कहा कि प्रियंका कम से कम सदन में बैठकर चर्चा सुनती हैं और बहस में भाग लेती हैं। उनके इस बयान को कई सांसदों ने राहुल गांधी पर अप्रत्यक्ष तंज के रूप में देखा। रिजजू के इस बयान के दौरान प्रियंका गांधी बाड़ा अपनी सीट पर बैठकर मुस्कुराती नजर



आईं। यह दृश्य भी सदन में चर्चा का विषय बन गया। रिजजू ने स्वयं इस मुस्कान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी की यह मुस्कुराहट शायद उनके बयान का संकेत दे रही है। जब बाद में उन्हें बोलने का अवसर मिला तो प्रियंका ने उसी मुस्कुराहट को अपने जवाब की शुरुआत बना दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें हंसी इसलिए आई क्योंकि जो लोग दिन-रात देश के पहले प्रधानमंत्री Jawaharlar Nehru की आलोचना करते रहते हैं, वही आज अपने तर्कों को मजबूत करने के लिए नेहरू के बयानों का सारा लेते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह देखकर उन्हें आश्चर्य भी हुआ और थोड़ी खुशी भी हुई कि कम से कम इस बहाने नेहरू जी के विचारों को स्वीकार तो किया जा रहा है। इसके बाद प्रियंका गांधी ने अपने भाई और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का खुलकर बचाव किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में राहुल गांधी ही वह नेता हैं जिन्होंने सत्ता के सामने झुकने

से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सदन में हमेशा बेहिंसाक अपनी बात रखते हैं और जो सच उन्हें दिखाता है, उसे कहने से पीछे नहीं हटते। उनके अनुसार यही कारण है कि सत्ता पक्ष को उनकी बात अस्सर कड़वी लागती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना और जनता की आवाज उठाना होता है, और राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं। इस दौरान सदन का माहौल कई बार हल्की हंसी और तालियों से भी गुंजता रहा। कई सांसदों को यह संवाद दिलचस्प लगा क्योंकि इसमें राजनीतिक तंज के साथ-साथ व्यक्तित्व शैली भी नजर आई थी। हालांकि दोनों को मजबूत करने के लिए नेहरू के बयानों का सारा लेते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह देखकर उन्हें आश्चर्य भी हुआ और थोड़ी खुशी भी हुई कि कम से कम इस बहाने नेहरू जी के विचारों को स्वीकार तो किया जा रहा है। इसके बाद प्रियंका गांधी ने अपने भाई और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का खुलकर बचाव किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में राहुल गांधी ही वह नेता हैं जिन्होंने सत्ता के सामने झुकने

स्वीकार कर रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में नेहरू की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को महत्व देना जरूरी होता है। यदि सरकार आलोचना को स्वीकार नहीं करेगी तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो जाएगी। उनके अनुसार विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाना या उनकी बातों को नजरअंदाज करना किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। दूसरी ओर किरण रिजजू ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि सरकार विपक्ष की आलोचना से डरती नहीं है, लेकिन बहस और चर्चा जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद वह स्थान है जहां सभी पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलता है और यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। सदन में हुई इस बहस ने यह भी दिखाया कि भारतीय राजनीति में तीखी असहमति के बावजूद संवाद की परंपरा अभी भी कायम है। एक ओर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विचारों का स्पष्ट टकराव दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर संसदीय मर्यादों के भीतर रहकर जवाब देना भी भारतीय लोकतंत्र की खास पहचान है। इस पूरे घटनाक्रम ने कुछ समय के लिए प्रियंका गांधी की कार्यवाही को रोचक बना दिया। कई सांसदों ने इसे संसदीय राजनीति की जीवंतता का उदाहरण बताया।

ऊर्जा सहयोग की नई मिसाल: भारत से पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश पहुंचा 5000 टन डीजल

जीएनएस)। ढाका। वैश्विक स्तर पर बढ़ती ऊर्जा चुनौतियों और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग को मजबूत करते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत से पाइपलाइन के माध्यम से लगभग 5,000 टन डीजल बांग्लादेश भेजा गया है, जो दोनों देशों के बीच हुए दीर्घकालिक ऊर्जा आपूर्ति समझौते का हिस्सा है। इस आपूर्ति को क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा और द्विपक्षीय सहयोग की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुआ है। दोनों देशों ने तेल, गैस और बिजली के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर मिलकर काम किया है। इसी कड़ी में डीजल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन के जरिए ईंधन भेजने की व्यवस्था शुरू की गई थी, ताकि बांग्लादेश को नियमित और स्थिर आपूर्ति मिल सके। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के चेयरमैन Muhammad Rezanur Rahman ने इस संबंध में जाकारा देते हुए बताया कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक दीर्घकालिक समझौता हुआ है जिसके तहत हर वर्ष लगभग 1,80,000 टन डीजल पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत आज जो 5,000 टन डीजल बांग्लादेश पहुंच रहा है, वह उसी वाणिज्य आपूर्ति का हिस्सा है। भारत को यह खेप भारत से पाइपलाइन के



माध्यम से बांग्लादेश के परबतिपुर क्षेत्र में पहुंचाई जा रही है। यह मार्ग दोनों देशों के बीच स्थापित ऊर्जा अवसरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। पाइपलाइन के जरिए ईंधन की आपूर्ति होने से परिवहन लागत कम होती है और आपूर्ति भी अधिक सुरक्षित तथा तेज हो जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों के कारण कई देशों को ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंत बनी हुई है। ऐसे समय में भारत का यह कदम न केवल बांग्लादेश के लिए रहत लेकर आया है, बल्कि दक्षिण एशिया में भी धेखा जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को यह पहल केवल ईंधन आपूर्ति तक सीमित नहीं है। दोनों देश बिजली उत्पादन और बिजली व्यापार के क्षेत्र में भी साझेदारी कर रहे हैं। भारत से बांग्लादेश को बिजली निर्यात की

व्यवस्था पहले से ही चल रही थी और इससे बांग्लादेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है। राजनीतिक विरोधों के बावजूद भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध पिछले एक दशक में काफी मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री Narendra Modi और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री Sheikh Hasina के नेतृत्व में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के कई नए रास्ते खोले हैं। व्यापार, परिवहन, ऊर्जा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच विश्वास और साझेदारी बढ़ी है। डीजल पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति की व्यवस्था भी इसी सहयोग का परिणाम है। इससे पहले बांग्लादेश को भारत से ईंधन टैंकरों के जरिए भेजा जाता था, जिसमें समय और लागत दोनों अधिक लगते थे। पाइपलाइन के शुरू होने के बाद यह प्रक्रिया कहीं अधिक सरल और प्रभावी हो गई है। बांग्लादेश के लिए डीजल एक महत्वपूर्ण ईंधन है जिसका उपयोग बिजली उत्पादन, कृषि कार्यों और परिवहन क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जाता है। देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था और औद्योगिक गतिविधियों के कारण ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पड़ोसी देश से स्थिर और नियमित आपूर्ति मिलना उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की परियोजनाएं केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं रहती, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग को भी मजबूत बनाती हैं। दक्षिण एशिया में कई देशों के बीच ऊर्जा संबंधों का साझा उपयोग भविष्य में क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत के लिए भी यह पहल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। पड़ोसी देशों के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाने से भारत की भूमिका मजबूत होती है और आपसी भरोसे का वातावरण भी बनता है। इससे व्यापार और निवेश के नए अवसर भी पैदा होते हैं। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में इस तरह की ऊर्जा परियोजनाओं को और विस्तार दिया जा सकता है। यदि दोनों देशों के बीच सहयोग इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में ऊर्जा आपूर्ति की क्षमता और भी बढ़ाई जा सकती है। कुल मिलाकर भारत से पाइपलाइन के जरिए भेजा गया यह 5,000 टन डीजल केवल एक प्रभाव है। बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग निर्यात आपूर्ति नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया में सहयोग, विश्वास और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ऐसे समय में जब दुनिया के कई हिस्सों में ऊर्जा संकट की स्थिति बनी हुई है, भारत और बांग्लादेश के बीच यह साझेदारी क्षेत्रीय सहयोग का एक सकारात्मक उदाहरण बनकर सामने आई है।

“न्यूक्लियर पावर और AI भारत को \$30 ट्रिलियन की इकॉनमी बना सकते हैं”ः कुशाग्र बजाज

बजाज समूह के चेयरमैन और उनकी बेटी ने जय हिंद कॉलेज के फैमिली मैनेज्ड बिजनेस हब द्वारा आयोजित “मेगा नेटवर्किंग मीट- 2026” में युवा एंटरप्रेन्योर्स को दिये सफलता के मंत्र

जीएनएस)। मुंबई। देश के प्रमुख औद्योगिक समूह बजाज ग्रुप के चेयरमैन कुशाग्र बजाज ने कहा कि न्यूक्लियर पावर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत की दूरगामी इकॉनमी ग्रोथ को बढ़ाने वाली दो सबसे जरूरी इंस्ट्रूमेंट के तौर पर उभर सकती हैं, जिनसे आने वाले दशकों में देश को \$5 ट्रिलियन की इकॉनमी से \$30 ट्रिलियन की इकॉनमी तक बढ़ाने में महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है।



श्री बजाज ने यह बात जय हिंद कॉलेज के फैमिली मैनेज्ड बिजनेस हब द्वारा आयोजित “मेगा नेटवर्किंग मीट- 2026” में बोलते हुए कही, जहाँ उन्होंने अपनी बेटी और बजाज समूह की पहली महिला उच्च अधिकारी सुश्री आनंदमयी बजाज के साथ स्टूडेंट्स, फैकल्टी और एल्युमनाई एंटरप्रेन्योर्स से बातचीत की और उन्हें अपने कैरियर में सफलता के मंत्र दिये। श्री बजाज ने कहा कि न्यूक्लियर पावर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के आर्थिक भविष्य को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभायेंगे। उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर पावर बिजनेस में आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि AI युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मौका है क्योंकि इसमें प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और एनर्जी सिक्वोरिटी को काफी तेजी से बढ़ाने की क्षमता है, जिसके फलस्वरूप भारत \$30 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने पीढ़ियों तक फैमिली एंटरप्राइज को बनाए रखने में मूल्यों और अनुशासन के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कंसिस्टेंसी, कड़ी मेहनत, पढ़ना और गहराई से सोचने



की क्षमता फैमिली बिजनेस को जिम्मेदारी से बनाए रखने और उसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिजनेस परिवारों को अपनी पीढ़ी को मजबूत अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना के साथ बढ़ा करना चाहिए, ताकि वे समझ सकें कि एक एंटरप्राइज बनाने और उसे बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? लीडरशिप और सीखने पर अपना नजरिया शेयर करते हुए, बजाज ग्रुप की पांचवीं पीढ़ी की युवा लीडर, सुश्री आनंदमयी बजाज ने स्ट्रेटजिक सोच को आकार देने में ग्लोबल एक्सपोजर और लगातार सीखने की वैल्यू के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अपने कम्पर्ट ज़ोन से बाहर निकलने के फलस्वरूप दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। उन्होंने कहा कि विदेश में पढ़ाई करने से मेरा नजरिया बढ़ा हुआ और मुझे अलग-अलग आइडिया और अनुभवों के लिए ज़्यादा खुला होने में मदद मिली। उन्होंने फैमिली बिजनेस को प्रोफेशनल बनाने के महत्व पर भी जोर दिया ताकि आपकी पीढ़ी अनुभवी इंस्ट्रूमेंट लीडर्स और प्रोफेशनल्स से सीख सके। उन्होंने बताया कि फैमिली बिजनेस को प्रोफेशनल बनाने से ऑर्गनाइजेशन के अंदर अनुभवी लीडर्स और एक्सपर्ट्स से सीखने का उल्लेखनीय मौका मिलता है। उन नजरियों के लिए खुला रहना और ज़मीनी स्तर पर सीखना, सोच-समझकर स्ट्रेटिजिक फैसले लेने और जरूरी समझ विकसित करने के लिए नितांत आवश्यक है। इस इवेंट के ऑडियंस में मिसेज वासवदत्ता बजाज भी मौजूद थीं, जो अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व में बजाज परिवार की

गर्वी गुजरात हिन्दी

JioTV CHENNAI NO. 2002

Jio FIBER, Jio tv+, Jio Fiber, Daily Hunt, ebaba Tv, Dish Plus, Jio Air Fiber, Jio tv+, Jio Fiber, DTH live OTT, Rock TV, Airtel, Amezone Fire, Roku Tv-US.UK



संपादकीय टी-ट्वेंटी में बादशाहत

एक बार फिर भारत ने क्रिकेट के सबसे छोटे स्वरूप टी-20 में अपनी सर्वोच्चता साबित की है। हालांकि, भारत के हर क्षेत्र में शानदार खेल ने दर्शकों को फाइनल मुकाबले के रोमांच से वंचित किया, लेकिन भारतीय टीम ने हर क्षेत्र में बेजोड़ श्रेष्ठता प्रदर्शित की। भारतीय टीम निर्भीकता से खेली। मुख्य कोच गौतम गंभीर का अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती को अनिश्चित फॉर्म के बावजूद महत्वपूर्ण फाइनल के लिये टीम में बरकरार रखना सही साबित हुआ। संजू सैमसन ने तीन सबसे महत्वपूर्ण मैचों में निर्णायक पारी खेली। वहीं चतुर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी का जादू बिखेरा। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, ईशान किशन, शिवम दुबे ने महत्वपूर्ण अवसरों पर योगदान दिया। यह अच्छी बात है कि सुपर आठ के एक मैच में दक्षिण अफ्रीका से मिली करारी हार को भारतीय टीम ने एक सबक के तौर पर लिया। जिससे टीम को जीत की लय में वापस आने में सहायता मिली। यह सुखद ही है कि दो साल से भी कम समय में भारतीय टीम ने टी-20 विश्व कप के दो खिताब हासिल किए। निस्संदेह, इस उल्लेखनीय उपलब्धि में इंडियन प्रीमियर लीग में टी-20 मैचों का लगातार अभ्यास जीत की लय बनाये रखने में मददगार साबित हुआ। क्रिकेट के दीवाने इस देश में प्रीमियर लीग ने क्रिकेट प्रतिभाओं को अपने खेल में निखार लाने का एक बेहतर अवसर उपलब्ध कराया। यह शानदार जीत, भारत द्वारा वनडे चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के टीक एक साल बाद मिली है। लेकिन एक अंतर्विरोध यह भी है कि सफेद गेंद के क्रिकेट और व्यावसायिक खेल के इस मिश्रण ने टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम की कमजोरी को उजागर किया है। जिसका उदाहरण घरेलू सीरीज में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका से मिली करारी हार है, जो हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। यह एक हकीकत है कि जब तक भारत टेस्ट मैचों में अपनी स्थिति मजबूत नहीं करता, तब तक भारत का वैश्विक क्रिकेट में पूरी तरह वचस्व हासिल करना संभव न होगा। कमोवेश, महिला टीम के मामले में भी यही बात लागू होती है, जिसने पिछले साल नवंबर में वनडे विश्व कप जीता। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में इस टीम को पकड़ भी ढीली हुई है। वास्तव में दोनों टीमों को क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में संतुलित कामयाबी के साथ ही आगे बढ़ना होगा। इस हकीकत को जानते हुए कि खेल जगत के परिप्रेक्ष्य में क्रिकेट का दबदबा हमेशा बना रहना है, अब चाहे टीमें अच्छा खेलें या कमजोर। भारत में उपलब्ध क्रिकेट के समृद्ध संसाधनों और लगातार सामने आती नई प्रतिभाओं के चलते आईसीसी की तमाम प्रतियोगिताओं में भारतीय दबवा आने वाले वर्षों में भी बना रह सकता है। इस टी-20 विश्वकप में भारतीय जीत को इसी नजरिये से देखने की जरूरत है। लेकिन जरूरत इस बात की होगी कि व्हाट बॉल के साथ भारतीय टीम ब्रेड बॉल क्रिकेट में अपना वचस्व बनाये रखे। टीम वनडे और टी-20 के साथ टेस्ट क्रिकेट में भी तमाम परिस्थितियों के बावजूद जीत का जज्बा बनाये रखे। इस टूर्नामेंट में संजू सैमसन द्वारा दिखाया गया खेल भारतीय टीम के लिये निर्णायक साबित हो सकता है। जिन्होंने तीन महत्वपूर्ण मैचों में अस्सी से अधिक रन बनाकर जीत में अहम भूमिका निभायी है। लंबे समय तक उपेक्षित रहने के बावजूद जब उन्हें परिस्थितिवश खेलने का मौका मिला तो उन्होंने अवसर का भरपूर लाभ उठाकर खुद को साबित किया। वे सिर्फ पांच मैच खेलने के बावजूद टूर्नामेंट के सबसे शानदार खिलाड़ी का खिताब हासिल करने में कामयाब रहे। इसी तरह टूर्नामेंट में किफायती रन रेट के साथ निर्णायक विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह की उपलब्धियां भी कम नहीं रहीं। विश्वी टीम के खिलाड़ियों पर ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में भी कामयाब रहे। वे मैच की दिशा बदलने वाले गेंदबाज भी साबित हुए। निर्णायक फाइनल मैच में तीन विकेट लेने वाले अक्षर पटेल के योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन अभी भी टीम को अपनी फील्डिंग में चुस्ती लाने की जरूरत है ताकि फिर किसी टूर्नामेंट में एक दर्जन से अधिक कैच छोड़ने की तोहमत न लगे। बहरहाल, नए क्रिकेटरों की ऊर्जा इस टूर्नामेंट में भारत का पलड़ा भारी करने में खासी मददगार साबित हुईं।

अभियान

आत्मा की गहराइयों में छिपा है ईश्वर का मार्ग

मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे प्राचीन और गहरे प्रश्नों में एक प्रश्न हमेशा से रहा है—ईश्वर क्या है, वह कहाँ रहता है, उसका स्वयं कैसा है और मनुष्य उसे कैसे प्राप्त कर सकता है। यह प्रश्न केवल धर्म या दर्शन का विषय नहीं है, बल्कि मनुष्य के अस्तित्व और उसकी जिज्ञासा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जब भी मनुष्य इस विशाल ब्रह्मांड को देखता है, प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था को समझने की कोशिश करता है या अपने जीवन के सुख-दुख पर विचार करता है, तब उसके भीतर यह जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से जाग उठती है कि इस समस्त सृष्टि के पीछे कौन-सी शक्ति कार्य कर रही है। यद्यपि इन प्रश्नों का अंतिम और पूर्ण उत्तर देना आसान नहीं है, फिर भी हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों, तर्कविदों, संतों और दार्शनिकों ने अपने अनुभव, साधना और गहन चिंतन के आधार पर इन रहस्यों को समझने और समझाने का प्रयास किया है।

भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने ईश्वर को समझने के लिए किसी एक सीमित विचार को अंतिम सत्य नहीं माना। यहाँ विविध दृष्टिकोणों और सिद्धांतों को स्वीकार किया गया है। स्नातन परंपरा में ईश्वर को लेकर द्वैत और अद्वैत

“

नेपाली मन:स्थिति

हम भारतीयों से भिन्न नहीं है। जितनी जल्दी

हम हतोत्साहित

होते हैं, उसी त्वरा

से हम उत्साहित भी

महसूस करते हैं।

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी

(रास्वापा) जिसका

जन्म 2017 में हुआ

था, जो अपने जन्म के

छह महीने के भीतर

आम चुनाव में चौथी

पार्टी के रूप में उभरी

थी। अब यही राष्ट्रीय

स्वतंत्र पार्टी अभूतपूर्व

जीत के साथ अति

उत्साह में है।

प्रेरणा

गलतियों से जन्म लेती है सफलता की असली रोशनी

मानव जीवन में सफलता का सपना लगभग हर व्यक्ति देखता है। कोई आर्थिक समृद्धि चाहता है, कोई समाज में प्रतिष्ठा, तो कोई अपने कार्यक्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना चाहता है। परंतु जब सफलता की बात आती है तो अक्सर लोग यह समझ लेते हैं कि यह केवल भाग्य या असाधारण प्रतिभा का परिणाम होती है। जबकि सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी और प्रेरणादायक है। सफलता का असली रहस्य उन अनुभवों में छिपा होता है जो मनुष्य अपनी गलतियों, संघर्षों और निरंतर प्रयासों से प्राप्त करता है। इतिहास में अनेक ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपनी असफलताओं को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाया और उन्हीं से सीखकर जीवन में अद्भुत ऊँचाइयों हासिल कीं।

इसी संदर्भ में अमेरिका के एक प्रसिद्ध उद्योगपति मिस्टर कारनेगी का एक प्रसंग अत्यंत प्रेरणादायक माना जाता है। उनका नाम दुनिया के उन महान उद्योगपतियों में गिना जाता है जिन्होंने अपने परिश्रम, दूरदृष्टि और निर्णय क्षमता से एक विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित किया। एक दिन एक जापानी इंजीनियर उनके कारखाने का निरीक्षण करने आया। उसने कारखाने की व्यवस्था, अनुशासन और कार्यशैली को बहुत ध्यान से देखा। वह यह देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ कि किस प्रकार एक साधारण विचार को इतना बड़ा औद्योगिक रूप दिया जा सकता है।

जब भोजन का समय आया तो वह इंजीनियर मिस्टर कारनेगी के साथ बैठे। उसके मन में एक जिज्ञासा लंबे समय से चल रही थी। उसने विनम्रता से पूछा, “सर,

हाल ही में, नेपाली राजनीतिक हलकों में एक पदहली बार नहीं हुआ, “पॉप्युलिज़्म”। लोकलुभावनवाद कोई नया शब्द नहीं है। यह शब्द लैटिन में इस्तेमाल, “पॉपुलस” से आया है, जिसका अर्थ है, ‘लोग’। 18वीं शताब्दी के मध्य में रूस के जार को उखाड़ फेंकने के लिए हुए ‘नरोदनिकी आंदोलन’ ने ‘लोकलुभावनवाद’ शब्द को एक राजनीतिक रूप दिया। रूसी में ‘नरोद’ का अर्थ है, ‘आदमी’। हालांकि, यह माना जाता है कि अमेरिका में इस शब्द का राजनीतिक विस्तार अमेरिकन पीपुल्स पार्टी द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना 1890 में हुई थी।

मोनाशा यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर बेंजामिन मोफिट की पुस्तक ‘द ग्लोबल राइट ऑफ पॉपुलिज़्म’, 2016 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसके प्रकाशन के समय विश्व राजनीति ध्रुवीकरण की अवधि से गुजर रही थी, जिसे ब्रिटेन में ब्रेक्सिट, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प का उदय और यूरोप, लैटिन अमेरिका में दक्षिणपंथी व वामपंथी ताकतों के प्रारम्भ और पतन द्वारा चिह्नित किया गया था। लेखक बेंजामिन मोफिट ने राजनीति को ग्लैमर या शैली के रूप में वर्णित किया है, जिसकी पसंद लगभग नेपाली राजनीतिक हस्तियों के समान है। शैली, स्वाद, भोजन, चलने, बोलने या समग्र लोकलुभावन कल्पना के अनुरूप।

इस हिमालयी देश में चुनावों ने एक तरह से स्पष्ट जवाबदाश दिया है, अब केवल घोषणापत्र के वादों को लागू करना बाकी है। नेपाली मतदाताओं ने मुख्यधारा के दलों के भविष्य को लगभग सोल कर दिया है। समाजवादी टोपी हर किसी के लिए उपयुक्त है, लेकिन लोकलुभावन टोपी हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। बालेन, रवि और गगन की तरह हर कोई लोकप्रिय होना चाहता है। क्योंकि, डिजिटल फ़्रेम की लोकप्रियता ने

प्रेरणा

गलतियों से जन्म लेती है सफलता की असली रोशनी

आपने इतना विशाल औद्योगिक साम्राज्य खड़ा किया है। आपकी इस अद्भुत सफलता का रहस्य क्या है?” यह प्रश्न सुनकर कारनेगी मुस्कराए और बहुत सरल शब्दों में उत्तर दिया, “सही समय पर सही निर्णय लेना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है।” इंजीनियर को यह उत्तर सुनकर संतोष तो हुआ, परंतु उसकी जिज्ञासा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसने तुरंत दूसरा प्रश्न किया, “सर, आप सही निर्णय कैसे ले पाते हैं?” कारनेगी ने शांत स्वर में कहा, “अनुभवों के आधार पर।” यह उत्तर भी सरल था, लेकिन इसके पीछे गहरा जीवन दर्शन छिपा हुआ था। अब इंजीनियर के मन में तीसरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने पूछा, “आपने इतने अनुभव प्राप्त कैसे किए?” इस बार कारनेगी ने इंजीनियर के कंधे पर स्नेहपूर्वक हाथ रखा और कहा, “बेटा, अनुभव गलत निर्णयों के दुष्परिणामों से मिलते हैं। जीवन में जब हम गलतियाँ करते हैं और उनके परिणामों से सीखते हैं, तभी वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है। लेकिन एक बात याद रखो, उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। यही संकल्प हमें आगे बढ़ता है और यही अनुभव तथा कठोर प्रयास हमें सफलता के शिखर तक पहुंचाते हैं।”

कारनेगी के ये शब्द सुनकर जापानी इंजीनियर कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। उसे समझ में आ गया कि सफलता का मार्ग केवल प्रतिभा या अवसरों से नहीं बनता, बल्कि यह निरंतर सीखने और स्वयं को सुधारने की प्रक्रिया से बनता है। चंद शब्दों में उसने संसार के एक महान उद्योगपति की सफलता का मूल रहस्य समझ

लिया था। वास्तव में जीवन की यही सच्चाई है कि गलतियाँ मनुष्य की सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से घबराता नहीं, बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़ता है, वही अंततः सफलता के शिखर पर पहुंचता है। असफलता हमें यह सिखाती है कि हमने कहाँ गलती की, किस दिशा में सुधार की आवश्यकता है और आगे किस प्रकार अधिक सावधानी और समझदारी से कदम उठाए जा सकते हैं। दुनिया के अधिकांश महान व्यक्तियों का जीवन इसी सिद्धांत का प्रमाण है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बार असफलताओं का सामना किया, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया, उनसे सीख ली और फिर नए उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। यही कारण है कि अंततः उन्होंने असंभव प्रतीत होने वाली ऊँचाइयों को भी प्राप्त कर लिया।

सफलता प्राप्त करने के लिए केवल बड़े सपने देखना पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए धैर्य, परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित होता है, तब वह हर चुनौती को सीखने का अवसर मानता है। धीरे-धीरे उसके अनुभव बढ़ते जाते हैं और वही अनुभव उसे सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। आज के आधुनिक युग में भी यह सिद्धांत उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। चाहे व्यवसाय हो, शिक्षा या कठिन साधना की आवश्यकता नहीं होती। इसमें केवल सच्चे प्रेम और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। कहा भी गया है कि भगवान् भाव के भूखे होते हैं। यदि मन में सच्चा प्रेम और श्रद्धा हो तो ईश्वर की कृपा प्राप्त करना कठिन नहीं होता। योग के माध्यम से मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ रखता है, अपने मन को नियंत्रित करता है और अपनी चेतना को उच्च स्तर तक ले जाने का प्रयास करता है। योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक समूर्ण पद्धति है जिसमें संयम, संतुलन और आत्मनियंत्रण का विशेष महत्व होता है। संतों और महात्माओं ने यह भी बताया है कि ईश्वर की अनुभूति का सबसे बड़ा मार्ग मन की शुद्धता है। जब तक मन विषय-वासनाओं, इच्छाओं और विकारों से भरा रहता है, तब तक मनुष्य के लिए ईश्वर का अनुभव करना कठिन हो जाता है। मनुष्य से ईश्वर को प्रति समर्पित कर देता है। वह ईश्वर को अपने मित्र, मार्गदर्शक और रक्षक मानता है। संतों ने भक्ति को सबसे सरल और सहज मार्ग बताया है, क्योंकि इसमें जटिल



जीवन की गुणवत्ता को स्क्रीन के अनुकूल बना दिया है।

नेपाली मन:स्थिति हम भारतीयों से भिन्न नहीं है। जितनी जल्दी हम हतोत्साहित होते हैं, उसी त्वरा से हम उत्साहित भी महसूस करते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (रास्वापा) जिसका जन्म 2017 में हुआ था, जो अपने जन्म के छह महीने के भीतर आम चुनाव में चौथी पार्टी के रूप में उभरी थी। अब यही राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी अभूतपूर्व जीत के साथ अति उत्साह में है। इनके शैदाई, ‘राम राज्य’ के सपने में डूबे हुए हैं। विवादों से घिरे भूतपूर्व पत्रकार रबी लामिछाने और रैंपर से राजनेता बने बालेन शाह की जोड़ी आ जाएगी कि सरकार गठन के लिए किसी दल-जमात की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेपाल की राजनीति के तीनों ‘बिग बी’, नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष गगन थापा, नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी

के चेयरमैन प्रचंड ने भी नहीं सोचा था कि निचले सदन ‘प्रतिनिधि सभा’ में केवल 17, सात, और आठ सीटें क्रमशः मिलेंगी। नेपाल के विश्लेषक इसे ‘नया शक्ति’ बोलते हैं। एक तरफ रवि लामिछाने द्वारा बनाया गया रास्वापा है, जिसमें उनका संगठनात्मक प्रभाव है। दूसरी ओर, बालेन की क्रेज़िक अभूतपूर्व जीत, रास्वापा की एक उन्मादी लहर पार्टी के रूप में उभरी थी। वैसी स्थिति में रवि-बालेन संबंध कब तक, कितना निभेगा? बड़ा सवाल है। नेपाली जनता ने इस पार्टी के पक्ष में वोट क्यों दिया? बहुत साफ़ है, कि मतदाता का धैर्य और विश्वास पुराने नेताओं पर से टूट चुका था। सोशल मीडिया पर विराजे कुछ तुक्केबाज कयास लगाते हैं कि यह चीन का किया धरया है। कुछ को शक अमेरिका पर है। लेकिन, सच यह है कि नेपाल के मतदाताओं ने मत पत्र के जरिये मौन सजा दी है। यह उन्होंने दुनिया भर में दर्ज कराया है, कि वॉलेट पेपर पर भरोसा

कीजिये। वही पदहली बार नहीं है, जब नेपाली राजनीति में एक वैकल्पिक शक्ति की खोज की गई। हर बार जब कोई राजनीतिक बदलाव होता है, तो लोग उत्साहित होते हैं। लेकिन, जब उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जाता है तो यह असंतोष और निराशा में रूपांतरित हो जाता है। 2007 से कांग्रेस परिवर्तन के साधन के रूप में चीन के बार-बार कहने के बावजूद, नेपाली वामपंथी एक होकर भी नहीं रहे। बाबुराम भट्टाराई ने माओवादियों को छोड़कर एक ‘नई शक्ति’ बनाने की कोशिश की। लेकिन, वह भी जमीन पर नकार दिए गए। नेपाल में वामपंथ की राजनीति में टूट, विलय बहुतें बार हुआ है। तराई के नेता कब किसके संग सोदेबाजी कर लें, उनका कोई भरोसा नहीं था। तो, पब्लिक कब तक बर्दाश्त करती? इस बार नेपाली संसद में युवा प्रतिनिधियों की संख्या 38 प्रतिशत हुई है। आप चाहें, इसे जैन-जी का कमाल समझें। 59 युवा सांसदों में से 51 आरएसपी के हैं। इस आयु वर्ग में नेपाली कांग्रेस के चार प्रतिनिधि हैं, जबकि सीपीएन-यूएमएल के दो प्रतिनिधि हैं। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के उम्मीदवार ने भी जीत हासिल की है। 2022 में निर्वाचित सांसदों में, सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व 51-60 आयु वर्ग से आया था, जबकि केवल 11 प्रतिशत सदस्य 40 वर्ष से कम आयु के थे। इसी तरह, 2017 के चुनावों से चुने गए सदन में केवल 13 प्रतिशत सदस्य थे, जो 40 वर्ष से कम उम्र के थे। 35 साल के बालेन शाह, सबसे कम उम्र के निर्वाचित प्रधानमंत्री होंगे। नेपाल पहली बार इस तरह का नवीर पेश कर रहा है। बालेन शाह भावनात्मक उबाल की उपज हैं। नेपाली समाज बालेन के बारे में बहुत कम जानता है। दिल्ली और पेइजिंग के लिए भी पहली है बालेन शाह। युवाओं के बीच रैंपर के रूप में चर्चित, काठमांडू के मद्यौर के रूप में बालेन शाह कितने सफल रहे? कोई वस्तुनिष्ठ अनुसंधान और विश्लेषण नहीं है। दूसरी ओर, उनके शुभचिंतक इस बात की सराहना नहीं करते कि उन्होंने काठमांडू का चेहरा बदल दिया। आलोचकों ने उन्हें एक ‘भगोड़ा’ कहा है, जो जिम्मेदारी से बचना है।

सऊदी अरब की मदद के लिए रणभूमि में उतर सकता है पाकिस्तान, युद्ध का दायरा और फैलेगा!

पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते सुरक्षा हालात के बीच पाकिस्तान एक बेहद जटिल सामरिक दुविधा में फंस गया है। सऊदी अरब और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने इस्लामाबाद के सामने यह कठिन सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वह अपने पुराने सहयोगी सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा या फिर क्षेत्रीय संतुलन बनाये रखने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असिम मुनीर के सऊदी दौरे ने इस बहस को और तेज कर दिया है।दरअसल ईरान द्वारा सऊदी अरब पर मिसाइल और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बिगड़ में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए सामरिक क्षति समझौते की परीक्षा शुरू हो गयी है। इस समझौते के अनुसार यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो दूसरा देश उसकी सुरक्षा में सहयोग करेगा। इस संकट के बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख असिम मुनीर ने रियाद में सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान से मुलाकात की। इस बैठक में ईरानी हमलों और क्षेत्रीय सुरक्षा हालात पर चर्चा की गयी। दोनों देशों ने साझा रक्षा समझौते के तहत संभावित कदमों पर विचार किया।

यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यदि पाकिस्तान सऊदी अरब का सैन्य समर्थन करता है तो वह सीधे ईरान के साथ टकराव की स्थिति में आ सकता है। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पहले से ही अस्थिर है और ऐसे में नया संघर्ष उसके लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। मगर यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि पाकिस्तान लंबे समय से सऊदी अरब का घनिष्ठ सहयोगी रहा है। सऊदी अरब ने आर्थिक सहायता और तेल आपूर्ति के माध्यम से कई बार पाकिस्तान की मदद की है। दूसरी ओर पाकिस्तान की ईरान के साथ लंबी सीमा लागती है और इन दोनों देशों के बीच भी सुरक्षा और ऊर्जा के सवाल हैं। ईरान शिया बहुल देश है कि इस संकट का एक महत्वपूर्ण पहलू पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति भी है। देश में सुन्नी और शिया समुदाय दोनों की बड़ी आबादी है। ईरान शिया बहुल देश है जबकि सऊदी अरब सुन्नी नेतृत्व वाला राष्ट्र है। ऐसे में यदि पाकिस्तान किसी एक पक्ष का खुला समर्थन करता है तो देश के भीतर सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका भी रहेगी। अयातुल्ला अली

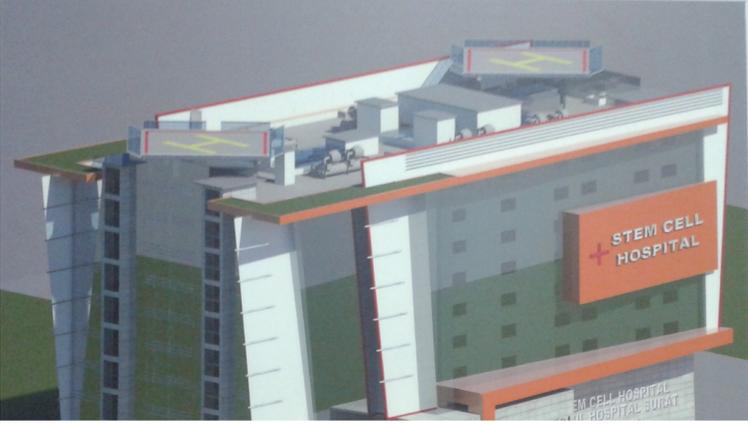
खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान के कई शहरों में शिया समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किये थे और गुस्ताई भीड़ ने पाकिस्तान स्थित अमेरिकी टकराव ने इस्लामाबाद के सामने यह कठिन सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वह अपने पुराने सहयोगी सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा या फिर क्षेत्रीय संतुलन बनाये रखने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असिम मुनीर के सऊदी दौरे ने इस बहस को और तेज कर दिया है।दरअसल ईरान द्वारा सऊदी अरब पर मिसाइल और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बिगड़ में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए सामरिक क्षति समझौते की परीक्षा शुरू हो गयी है। इस समझौते के अनुसार यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो दूसरा देश उसकी सुरक्षा में सहयोग करेगा। इस संकट के बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख असिम मुनीर ने रियाद में सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान से मुलाकात की। इस बैठक में ईरानी हमलों और क्षेत्रीय सुरक्षा हालात पर चर्चा की गयी। दोनों देशों ने साझा रक्षा समझौते के तहत संभावित कदमों पर विचार किया। यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यदि पाकिस्तान सऊदी अरब का सैन्य समर्थन करता है तो वह सीधे ईरान के साथ टकराव की स्थिति में आ सकता है। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पहले से ही अस्थिर है और ऐसे में नया संघर्ष उसके लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। मगर यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि पाकिस्तान लंबे समय से सऊदी अरब का घनिष्ठ सहयोगी रहा है। सऊदी अरब ने आर्थिक सहायता और तेल आपूर्ति के माध्यम से कई बार पाकिस्तान की मदद की है। दूसरी ओर पाकिस्तान की ईरान के साथ लंबी सीमा लागती है और इन दोनों देशों के बीच भी सुरक्षा और ऊर्जा के सवाल हैं। ईरान शिया बहुल देश है कि इस संकट का एक महत्वपूर्ण पहलू पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति भी है। देश में सुन्नी और शिया समुदाय दोनों की बड़ी आबादी है। ईरान शिया बहुल देश है जबकि सऊदी अरब सुन्नी नेतृत्व वाला राष्ट्र है। ऐसे में यदि पाकिस्तान किसी एक पक्ष का खुला समर्थन करता है तो देश के भीतर सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका भी रहेगी। अयातुल्ला अली

सूरत के नए सिविल अस्पताल में कुप्रशासन के आरोप: मरीजों को स्ट्रेचर और व्हीलचेयर जैसी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत का नया सिविल अस्पताल माजुरागेट के पास स्थित है। दक्षिण गुजरात और आसपास के इलाकों जैसे भरूच, नवसारी, वलसाड, अहवा, डांग, राजपीपला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से कई गरीब और मध्यम वर्ग के मरीज रोजाना इलाज के लिए इस अस्पताल में आते हैं। अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक अच्छी सेवा दे रहे हैं और मरीज ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन आरएमओ, अधीक्षक और चिकित्सा भंडार एवं सामान्य प्रशासन के प्रभारी अधिकारी अस्पताल के संचालन में पूरी तरह विफल रहे हैं।

अस्पताल के भंडार में स्ट्रेचर, व्हीलचेयर, गैड और चादरों का पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद, मरीज इन सुविधाओं से वंचित हैं। मरीजों को बदबूदार गैडों और चादरों पर सोना पड़ता है। मरीजों के परिवारों को खुद ही मरीजों को उठाना पड़ता है या स्ट्रेचर या व्हीलचेयर को खींचना पड़ता है। डेकेदार के कर्मचारियों को फर्जी हाजिरी लगाकर इलाज से वंचित रखा जाता है। अस्पताल के मुख्य द्वार के पास छाया में दवाइयों के लिए लंबी कतारें लगी रहती हैं। और अस्पताल का दवा बजट कहीं खर्च होता है? किसी को कोई जानकारी नहीं है।

शून्य एडिट विज्ञापन
अधिकांश डॉक्टर दवाइयों लिखते हैं जो अवैध रूप से प्राप्त की जा सकती हैं।



पहले सिविल अस्पताल में सभी प्रकार के इलाज और जांच मुफ्त में होते थे। अब, शासन परिवर्तन के कारण गरीब मरीजों को दवाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। जिस प्रकार वार्ड में भर्ती मरीजों को निजी अस्पताल में जाकर बाहर से दवाइयों खरीदनी पड़ती हैं, वही हाल सूरत के नए सिविल अस्पताल का भी है।

मरीज कल्याण समिति द्वारा मरीजों को दवाइयों मुहैया कराई जाती हैं। केंस पेपर और एक्स-रे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन,

प्रयोगशाला आदि सभी रिपोर्टों का शुल्क वसूला जाता है और यह पैसा मरीज कल्याण समिति में जमा किया जाता है। इसका प्रशासन इच्छानुसार चलता है। चूंकि मरीज कल्याण समिति की आय का कोई ऑडिट नहीं होता, इसलिए रिपोर्टें निजी ऑडिटों द्वारा ली जाती हैं। पिछले तीस वर्षों से डॉ. केतन नायक सूरत के नए सिविल अस्पताल में चिकित्सा अधिकांश समय मेडिकल स्टोर में बिताते

हैं। वर्तमान में वे आरएमओ के पद पर कार्यरत हैं। सूरत के नए सिविल अस्पताल के अधीक्षक की स्थायी नियुक्ति न होने के कारण डॉ. नायक सर्वसर्व की तरह कार्य कर रहे हैं और तानाशाही शासन चला रहे हैं। डॉ. नायक किस कृपा से तीस वर्षों से अधिक समय से लगातार सेवा कर रहे हैं? जब सरकार में अधिकारियों का आमतौर पर हर तीन साल में परिवर्तन होता है, तो यह नियम डॉ. नायक पर क्यों लागू नहीं होता ?

कूड ऑयल वायदा 657 रुपये फिसला: सोना वायदा 1.62 लाख रुपये और चांदी वायदा 2.78 लाख रुपये के स्तर पर पहुँचा

जोएनएस)। मुंबई: देश के अग्रणी कर्मोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कर्मोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 170656.07 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कर्मोडिटी वायदाओं में 31779.03 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कर्मोडिटी ऑप्शंस में 138875.71 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का मार्च वायदा 40264 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कर्मोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 6115.37 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 17759.96 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा 161743 रुपये पर खुलकर, ऊपर में 162388 रुपये और नीचे में 161340 रुपये पर पहुंचकर, 160299 रुपये के पिछले बंद के सामने 1701 रुपये या 1.06 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 162000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-गिनी मार्च वायदा 958 रुपये या 0.73 फीसदी की बढ़त के साथ 132163 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-पेटल मार्च वायदा 117 रुपये या 0.71 फीसदी की बढ़त के

साथ 16613 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। सोना-मिनी अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 161800 रुपये के भाव पर खुलकर, 162399 रुपये के स्तर के उच्च और 161301 रुपये के नीचेले स्तर को छूकर, 1614 रुपये या 1.01 फीसदी की बढ़त के साथ 161938 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-टेन मार्च वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 163779 रुपये के भाव पर खुलकर, 163779 रुपये के दिन के उच्च और 162100 रुपये के नीचेले स्तर को छूकर, 161402 रुपये के पिछले बंद के सामने 1248 रुपये या 0.77 फीसदी की बढ़त के साथ 162650 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा 271000 रुपये पर खुलकर, ऊपर में 278339 रुपये और नीचे में 271000 रुपये पर पहुंचकर, 267160 रुपये के पिछले बंद के सामने 7755 रुपये या 2.9 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 274915 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 7397 रुपये या 2.71 फीसदी की तेजी के संग 280355 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा



7439 रुपये या 2.73 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 280416 रुपये प्रति किलो पर आ गया। मेटल वर्ग में 2183.29 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मार्च वायदा 9.55 रुपये या 0.8 फीसदी की बढ़त के साथ 1203 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि जस्ता मार्च वायदा 1.7 रुपये या 0.52 फीसदी बढ़कर 326.9 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम मार्च वायदा 1.15 रुपये या 0.34 फीसदी औंधकर 334.8 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मार्च वायदा 45 पैसे या 0.24 फीसदी के सुधार के साथ 188.65 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 11715.69 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स कूड ऑयल मार्च वायदा 8437 रुपये पर खुलकर, ऊपर में 8459 रुपये और नीचे में 7846 रुपये पर पहुंचकर, 657 रुपये या 7.48 फीसदी गिरकर 8131 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। जबकि कूड ऑयल-मिनी मार्च वायदा 657 रुपये या 7.48 फीसदी औंधकर 8132 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। इनके अलावा नैचुरल गैस मार्च वायदा 290 रुपये पर खुलकर, ऊपर में 291.5 रुपये और नीचे में 281.2 रुपये पर पहुंचकर, 290.4 रुपये के पिछले बंद के सामने 1.7 रुपये या 0.59 फीसदी औंधकर 288.7 रुपये प्रति एमएमबीटीयू

पर आ गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मार्च वायदा 1.8 रुपये या 0.62 फीसदी गिरकर 288.7 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मार्च वायदा 972.1 रुपये पर खुलकर, 3 रुपये या 0.31 फीसदी औंधकर 970 रुपये प्रति किलो पर आ गया। कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 11273.02 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 6482.94 करोड़ रुपये की खरीद

बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 1509.10 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 431.36 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 4.29 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 236.26 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा कूड ऑयल और कूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 9711.21 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1996.97 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 6.80 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। ओपन इंटरस्ट सोना के वायदाओं में 10108 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 60701 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 50537 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 427384 लोट और गोल्ड-टेन के

वायदाओं में 60392 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 7025 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 18232 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 64913 लोट के स्तर पर था। कूड ऑयल के वायदाओं में 26622 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 25756 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 40312 पॉइंट के स्तर पर खुलकर, 40312 के उच्च और 40162 के नीचेले स्तर को छूकर, 609 पॉइंट बढ़कर 40264 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कर्मोडिटी ऑप्शंस अनियुक्त रूप में कूड ऑयल मार्च 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 222.7 रुपये की गिरावट के साथ 280 रुपये पर हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 290 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1 रुपये की गिरावट के साथ 21.05 रुपये हुआ। सोना मार्च 180000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 116.5 रुपये की गिरावट के साथ 538.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 40000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.5 रुपये की

गिरावट के साथ 869 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 5.1 रुपये की बढ़त के साथ 27.5 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 325 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 49 पैसे के सुधार के साथ 7.1 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में कूड ऑयल मार्च 8000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 229.7 रुपये की बढ़त के साथ 682.9 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.65 रुपये की बढ़त के साथ 17.6 रुपये हुआ। सोना मार्च 15000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 289 रुपये की गिरावट के साथ 757 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 20000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 267.5 रुपये की गिरावट के साथ 1313.5 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3.8 रुपये की गिरावट के साथ 23.67 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 92 पैसे के सुधार के साथ 4.7 रुपये हुआ।

कायाकल्प की ओर वटवा स्टेशन: पुनर्विकास कार्य तीव्र गति से जारी

वटवा रेलवे स्टेशन का बदला स्वरूप: नया स्टेशन भवन, 40 फीट चौड़ा FOB और लिफ्ट जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से होगा लैस, वटवा में बनेगा मेगा कोचिंग टर्मिनल, अहमदाबाद मण्डल से 150 से अधिक ट्रेनों का संचालन होगा संभव

जोएनएस)। पश्चिम रेलवे का अहमदाबाद मंडल यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं आधुनिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी विजन के अंतर्गत, 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत वटवा रेलवे स्टेशन का व्यापक पुनर्विकास कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। लगभग 33.64 करोड़ की अनुमानित लागत से किए जा रहे इन कार्यों का मुख्य उद्देश्य स्टेशन को न केवल एक परिवहन केंद्र बनाना है, बल्कि इसे शहर के एक आधुनिक 'सिटी सेंटर' के रूप में विकसित करना है।

इसके साथ ही वटवा में लगभग 3 किलोमीटर लंबे मेगा कोचिंग टर्मिनल का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसके निर्माण से अहमदाबाद क्षेत्र में ट्रेन संचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा भविष्य में कई नई ट्रेनों के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 20 नई परीक्षण (एक्जामिनेशन) लाइनों तथा 40 से अधिक स्टेबलिंग लाइनों का निर्माण किया जाएगा। कुल मिलाकर लगभग 100 लाइनों का विशाल कोचिंग कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा, जो देश के सबसे बड़े टर्मिनलों में से एक होगा।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना का डीपीआर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), अहमदाबाद द्वारा तैयार कराया जा रहा है। यह परियोजना न केवल रेलवे अवसंरचना को सुदृढ़ करेगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास और यात्री सुविधाओं में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।

मुख्य विकास कार्य: एक नई पहचान
स्टेशन के बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कार्य संपन्न किए जा रहे हैं:
नया स्टेशन भवन: लगभग 6,469 वर्गफुट क्षेत्र में एक भव्य और आधुनिक स्टेशन भवन का निर्माण किया गया है। जिससे टिकटिंग, पूराछाछ एवं अन्य यात्री सेवाएँ अधिक सुचारु रूप से उपलब्ध होंगी।
विशाल सक्कुलेंटिंग एरिया एवं पार्किंग: यातायात की भीड़भाड़ को नियंत्रित करने



हेतु 2,19,584 वर्गफुट के विशाल क्षेत्र में पार्किंग और सक्कुलेंटिंग एरिया विकसित किया गया है। इससे निजी और सार्वजनिक वाहनों के आवागमन में सुगमता आएगी।
कवर शेड एवं कैनोपी: यात्रियों को प्रतिकूल मौसम (धूप एवं वर्षा) से बचाने के लिए 13,627 वर्गफुट की कैनोपी और प्लेटफॉर्मों पर 13,164 वर्गफुट क्षेत्र में कवर शेड का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

आरामदायक प्रतीक्षा कक्ष: यात्रियों के लिए 926 वर्गफुट में अत्याधुनिक वेंटिंग हॉल बनाया गया है, जहाँ बैठने की उच्चतम व्यवस्था होगी।
प्लेटफॉर्म सुदृढ़ीकरण: लगभग 12,056 वर्गफुट क्षेत्र में प्लेटफॉर्म सरफेसिंग का कार्य किया गया है, जिससे यात्रियों को चलने-फिरने में आसानी होगी।
द्वितीय प्रवेश द्वार (Second Entry): यात्रियों की सुविधा के लिए 2,583 वर्गफुट क्षेत्र में द्वितीय प्रवेश द्वार का विकास किया गया है।
स्वच्छता एवं जल व्यवस्था: प्लेटफॉर्मों पर 4 नए आधुनिक शौचालय ब्लॉक और स्वच्छ पेयजल हेतु नए वाटर बूथ बनाए जा रहे हैं।

स्टेशन को पूरी तरह बाधा रहित

(Barrier-free) बनाने के लिए बड़े स्तर पर इकास्ट्रक्चर का कार्य चल रहा है:

विशाल पुट ओवर ब्रिज (FOB): यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए 40 फीट चौड़ा एक नया पुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। यह ब्रिज न केवल प्लेटफॉर्मों को जोड़ेगा, बल्कि स्टेशन के दोनों छोरों के बीच सुगम आवाजाही भी सुनिश्चित करेगा।

समावेशी सुविधा (लिफ्ट और दिव्यांगजन सुविधा): प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट की स्थापना का कार्य अंतिम चरणों में है। यह सुविधा विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए वरदान साबित होगी। वटवा रेलवे स्टेशन के इस पुनर्विकास से न केवल रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, बल्कि यह स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी गति प्रदान करेगा। कार्यों के पूर्ण होने पर स्टेशन का स्वरूप एक आधुनिक, व्यवस्थित और स्वच्छ दिखाई देगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद, वटवा क्षेत्र से यात्रा करने वाले हजारों दैनिक यात्रियों को एक अधिक सुरक्षित, गरिमापूर्ण और सुखद यात्रा अनुभव प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार की उद्योग क्षेत्र में एक और प्रोत्साहक पहल

गांधीनगर स्थित ईक्व्यूडीसी में उद्योग राज्य मंत्री डॉ. जयरामभाई गामित के करकमलों से ऊर्जा लैबोरेटरी, कॉन्फ्रेंस रूम तथा प्रशिक्षण केन्द्र का उद्घाटन किया गया
नई ऊर्जा लैबोरेटरी शुरू होने से आधुनिक टेस्टिंग एवं गुणवत्ता मूल्यांकन सेवाएँ अधिक आसान बनेंगी
उद्योगों को अब उनके प्रोडक्ट्स तथा सिस्टम्स का स्थानीय स्तर पर ही परीक्षण करने की सुविधा मिलेगी
नया प्रशिक्षण केन्द्र एमएसएमई उद्योगों, स्टार्टअप्स तथा इलेक्ट्रिकल-एनर्जी क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को मार्गदर्शन एवं टैक्निकल सपोर्ट देगा

जोएनएस)। गांधीनगर : गुजरात सरकार के उद्योग एवं खान विभाग अंतर्गत कार्यरत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं बॉयल्टी डेवलपमेंट सेंटर (ईक्व्यूडीसी), गांधीनगर में ऊर्जा लैबोरेटरी, कॉन्फ्रेंस रूम तथा प्रशिक्षण केन्द्र का मंगलवार को उद्योग राज्य मंत्री डॉ. जयरामभाई सी. गामित के करकमलों से उद्घाटन किया गया। डॉ. गामित ने इस अवसर पर ईक्व्यूडीसी की नई सुविधाओं से संबंधित तर्कती का अनावरण किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने ऊर्जा लैबोरेटरी का प्रत्यक्ष निरीक्षण भी किया। इन नई सुविधाओं के प्रारंभ होने से राज्य में ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा तकनीकी क्षमता के विकास को नई गति मिलेगी। विशेषकर एमएसएमई उद्योगों, स्टार्टअप तथा इलेक्ट्रिकल-एनर्जी क्षेत्र से जुड़े उद्योगों के लिए यह केन्द्र महत्वपूर्ण मार्गदर्शन एवं तकनीकी सपोर्ट प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया, रिकल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आदि जैसे मंत्रों को आगे बढ़ा रहे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में उद्योगों, एमएसएमई और स्टार्टअप क्षेत्र में अनेक प्रोत्साहक पहलों की हैं और इसके अंतर्गत राज्य के उद्योग एवं खान विभाग ने उसके अधीनस्थ कार्यरत ईक्व्यूडीसी में राज्य के उद्योगों के लिए ये तीन महत्वपूर्ण पहलों की हैं।

उल्लेखनीय है कि गुजरात सरकार ने विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात के मंत्र के साथ औद्योगिक विकास को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया है। ईक्व्यूडीसी



में शुरू की गई ये नई सुविधाएँ राज्य के ऊर्जा क्षेत्र, एमएसएमई उद्योगों तथा टैक्निकल मानव संसाधन विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी और गुजरात को ऊर्जा कार्यक्षमता एवं औद्योगिक विकास में अग्रणी बनने में सहायक होंगी। ईक्व्यूडीसी में शुरू की गई इस ऊर्जा लैबोरेटरी में डिसकॉम केबल्स, एनर्जी मोटर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, इन्वोल्टेडर तथा अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरणों के लिए आधुनिक परीक्षण सुविधाएँ उपलब्ध

कराई गई हैं, जिनके परिणामस्वरूप ऊर्जा कार्यक्षमता, इलेक्ट्रिकल गुणवत्ता, टेस्टिंग तथा एनालिसिस जैसे कामकाज अधिक सरल बनेंगे और उद्योगों को उनके उत्पादों तथा सिस्टम्स का स्थानीय स्तर पर ही परीक्षण करने की सुविधा मिलेगी। राज्य में उद्योग तथा तकनीकी क्षमता विकास को प्रोत्साहन देने के लिए ईक्व्यूडीसी में स्थापित किया गया ट्रेनिंग सेंटर उद्योगों, उद्योगकारों, इंजीनियरों, तकनीशियनों तथा विद्यार्थियों के लिए कौशल विकास के एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। इस केन्द्र में ऊर्जा प्रबंधन, इलेक्ट्रिकल सुरक्षा, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा टेक्नोलॉजी एवं उद्योग क्षेत्र के लिए आधुनिक टैक्निकल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, आधुनिक कॉन्फ्रेंस रूम उद्योगकारों, विशेषज्ञों तथा नीति निर्माताओं के बीच संवाद तथा विचार-विमर्श के लिए उपयोगी बनेगा। उद्योग एवं ऊर्जा क्षेत्र में नए विचारों, टेक्नोलॉजी तथा नीतियों पर चर्चा के लिए यह सुविधा महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में उभरकर आएगी। इस कार्यक्रम में उद्योग एवं खान विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ममता वर्मा, उद्योग आयुक्त श्री स्वरूप पी. एवं उद्योग जगत के अग्रणी तथा उच्च प्रशासनिक अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे				
सामग्री प्रबंधन विभाग				
विभिन्न सामग्री आपूर्ति				
ई-प्रोक्योरमेंट टेंडर अधिसूचना संख्या: S/12/2026 दिनांक 06.03.2026				
क्र.नं.	टेंडर नंबर	बीजों का संक्षिप्त विवरण	मात्रा	टी.ओ.डी.
80	10251043	RCF इंग नंबर LW-71245 Alt 'd' कर्मोडिटी कर्मोडिटी अरिथि केबल	6777 नग	06-अप्रैल-26
81	27245038C	5 बैटरी से चलने वाली रैल वे चैफरिंग मशीन	172 नग	03-अप्रैल-26

EMD, खरीद पर रोक और टेंडर की शर्तों के बारे में डिटेल्स में जानकारी के लिए, कृपया वेबसाइट www.ireps.gov.in और www.indianrailways.gov.in पर जाएं। 1198 हमें ताईक करें: [facebook.com/WesternRly](https://www.facebook.com/WesternRly) • हमें ताईक करें: [X.com/WesternRly](https://www.x.com/WesternRly)

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल				
W/623/NIT/1		ई-टेंडरिंग नोटिस	दिनांक: 07.03.2026	
मण्डल रेल प्रबंधक/मण्डल कार्यालय (कार्यलेखा शाखा) पश्चिम रेलवे रतलाम भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिये "खुली निविदा" ई-निविदा के माध्यम से वेबसाइट www.ireps.gov.in पर आमंत्रित करते हैं। विवरण इस प्रकार है-				
क्र. सं.	ई-टेंडरिंग संख्या और कार्य का नाम	अनुमानित लागत रु	बयाना राशि रु	कार्य समापन अवधि
1	RTM-2025-26-119R1	90,31,074.35	1,80,600/-	12 माह
Dr Ambedkar Nagar (DADN) - Provision of new Integrated crew lobby, CTC Office, counselling room, TRS staff Room with parking & boundary wall at including electric work. Similar type of work: Construction of any Building Work. वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि: 07.03.2026. निविदा खुलने की तिथि: 30.03.2026.				
2	RTM-2025-26-179R	17,46,63,526.01	10,23,300/-	18 माह
1. Rajendra Nagar - Provision of stabling line at in connection with SIMHASTHA 2028. & 2. Lekoda - Upgradation of existing "D" class to "B" class in connection with Simhastha 2028 including electrical work. Similar type of work: 1.1 Definition Of Similar Work: -For Works involving Track works (Sch-A+B) = Rs.2,94,40,454.19 Similar nature of Work: Any Track work 1.2 Definition Of Similar Work: -For Works involving Building works (Sch-C+D) = Rs.5,42,31,154.62 Similar nature of Work: Construction of buildings work 1.3 Definition Of Similar Work: -Works involving Bridge works (Sch-D+E) = Rs.8,49,64,894.57 Similar nature of Work: Any Rail/Road Bridge work of opening more than 3.0 m. Note: In case of works to be done under running line, the tenderer should have the experience of carrying out work under running traffic 1.4 Works involving Electrical works (Sch-F) = Rs. 60,27,022.63 Similar nature of Work: Wiring/ Rewiring in buildings with associated electrical works like control gear and protection arrangements in residential buildings or service buildings or railway stations /yards or colony/highway lightings. OR Lighting arrangement in buildings, circulating area, yard, street etc. with associated electrical works. OR Wiring/Rewiring, Lighting arrangement in buildings with associated electrical works i.e The tenderer must have successfully completed or substantially completed any one of the following categories of work(s) during last 07 (seven) years, ending last day of month previous to the one in which tender is invited: (i) Three similar works each costing not less than the amount equal to 30% of advertised value of the tender, or (ii) Two similar works each costing not less than the amount equal to 40% of advertised value of the tender, or (iii) One similar work costing not less than the amount equal to 60% of advertised value of the tender.). वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि: 07.03.2026. निविदा खुलने की तिथि: 30.03.2026.				
3	RTM-2025-26-184	72,51,628.71	1,45,000/-	15 माह
Ratlam Division-HUT for the Pointsman / traffic assistant including electrical work. Similar type of work: Any Civil Engineering Work. वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि: 07.03.2026. निविदा खुलने की तिथि: 06.04.2026.				
4	RTM-2025-26-195	61,73,637.30	1,23,500/-	24 माह
OM-KNW Section -Supply of potable drinking water through tanker at Various stations & LC gates for 02 years. Similar type of work: Any Civil Engineering/Track Work. OR Supply of Ballast / Boulders. वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि: 07.03.2026. निविदा खुलने की तिथि: 08.04.2026.				
5	RTM-2025-26-196	8,45,26,954.25	5,72,600/-	24 माह
Nimach Depot - Supply of 50 mm size machine crushed stone ballast and loading in to hoppers at. (Total Quantity = 107000.00 Cum). Similar type of work: Any Civil Engineering/Track Work. OR Supply of Ballast / Boulders. वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि: 07.03.2026. निविदा खुलने की तिथि: 08.04.2026.				
6	RTM-2025-26-197	4,62,95,111.54	3,81,500/-	18 माह
Ratlam Division - Providing Type II quarter at Rajendra Nagar -12 No. and Rau -08 No (Total 20 Nos.) including electrical work. Similar type of work: Construction of any Building Work. वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि: 07.03.2026. निविदा खुलने की तिथि: 10.04.2026.				
अनुमानित मात्रा: As per tender schedule. निविदा पत्र का मूल्य रु.: शून्य। विस्तृत निविदा सूचना अर्हता शर्तें एवं अन्य शर्तें वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध हैं। DE/51/1501 हमें ताईक करें: facebook.com/WesternRly • हमें ताईक करें: X.com/WesternRly				

गुजरात में 'एसेट सेफ्टी मॉनिटरिंग पोर्टल' लागू होगा : सड़क, पुल, भवन सहित सभी सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर का होगा सतत निरीक्षण

▶▶ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का नागरिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय

जीएनएस)। गांधीनगर : नागरिकों की सुरक्षा और सार्वजनिक संरचनाओं के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एसेट सेफ्टी मॉनिटरिंग पोर्टल लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन अंतर्गत लिए गए इस निर्णय के साथ ही, अब राज्य में मौजूद सड़कों, पुलों, भवनों सहित सभी सरकारी एवं सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की राज्य स्तर से एकीकृत मॉनिटरिंग होगी, जिससे किसी भी इन्फ्रास्ट्रक्चर से आम जनता की सुरक्षा पर कोई संकट न आए। यह निर्णय केवल एक टेक्निकल इन्वेंशन नहीं, बल्कि शासन की संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समबद्ध जवाबदेही का सशक्त उदाहरण है। राज्य सरकार ने इस पहल के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि विकास के साथ-साथ सुरक्षा, गुणवत्ता और सार्वजनिक विश्वास; तीनों समान रूप से अनिवार्य हैं।



डेढ़ लाख से अधिक परिसंपत्तियाँ अब एकीकृत डिजिटल निगरानी में
राज्य सरकार के इस निर्णय को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की ओर से हाल ही में एक परिपत्र जारी किया गया है, जिसके अनुसार राज्य में मौजूद सड़कों, पुलों, सरकारी भवनों और अन्य नागरिक अधोसंरचनाओं सहित 1.5 लाख से अधिक

सार्वजनिक परिसंपत्तियाँ अब एक ही केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज होंगी। जीआईएस आधारित लोकेशन, फोटोग्राफ्स, संरक्षक अधिकारी का विवरण और विशिष्ट डिजिटल पहचान; यह संपूर्ण व्यवस्था परिसंपत्तियों के जीवन-चक्र की वैज्ञानिक एवं सतत निगरानी सुनिश्चित करेगी। इससे न केवल वर्तमान सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि भविष्य



की इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण प्रक्रिया भी डेटा-आधारित बनेगी।
मुख्यमंत्री की स्पष्ट प्राथमिकता :
'नागरिक सुरक्षा से कोई समझौता नहीं' मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की संवेदनशील प्रशासनिक सोच का केन्द्र बिंदु नागरिक सुरक्षा है। एसेट सेफ्टी मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा

कि किसी भी परिसंपत्ति की संरचनात्मक कमजोरी, निरीक्षण में देरी या मरम्मत की आवश्यकता अनदेखी न रह जाए। स्वचालित निरीक्षण कैलेंडर और रियल-टाइम अलर्ट प्रणाली प्रशासन को समय रहते कार्रवाई के लिए बाध्य करेगी। इसके अंतर्गत इस एकीकृत पोर्टल पर फील्ड अधिकारी डिजिटल लॉगिंग से निरीक्षण



रिपोर्ट और फोटोग्राफ्स अपलोड करेंगे। जिला कलेक्टर और महानगर पालिका आयुक्तों को साप्ताहिक, मासिक और त्रैमासिक समीक्षा करनी होगी। प्रभारी सचिव जिला भ्रमण के दौरान निर्देश देंगे। इस प्रकार, प्रशासन का हर स्तर एक ही डिजिटल निगरानी तंत्र से जुड़कर कार्य करेगा।
जीएडी का निगरानी प्रकोष्ठ : शीर्ष स्तर

से सीधी नजर सामान्य प्रशासन विभाग में गठित समर्पित परिसंपत्ति सुरक्षा निगरानी प्रकोष्ठ राज्य स्तर पर दैनिक निगरानी करेगा और मुख्य सचिव को नियमित रिपोर्ट देगा। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि मुख्यमंत्री की मंशा और जमीनी क्रियान्वयन के बीच कोई अंतर न रहे। इस प्रकार, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का एसेट सेफ्टी मॉनिटरिंग पोर्टल लागू करने का निर्णय गुजरात के प्रशासनिक इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध होगा। यह केवल एक पोर्टल नहीं, बल्कि सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय गुजरात की मजबूत आधारशिला समान है।

राज्य के शहरों में तालाबों और हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए गुजरात अर्बन डेवलपमेंट मिशन शुरू करेगा 'लेक एंड एयर वॉच' पहल

17 मनपा और 152 नपा क्षेत्रों में तालाबों और हवा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए सिस्टम लागू किया जाएगा

जीएनएस)। गांधीनगर: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत' के विजन को साकार करने के लिए गुजरात एक मुख्य ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात के शहरों को टिकाऊ और स्मार्ट बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन्होंने प्रयासों के तहत राज्य सरकार के शहरी विकास और शहरी गृह निर्माण विभाग के अंतर्गत राज्य-स्तरिय नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत गुजरात शहरी विकास मिशन (जीयूडीएम) तालाबों और हवा की गुणवत्ता की रियल टाइम निगरानी सुनिश्चित करने के लिए 'लेक एंड एयर वॉच' पहल शुरू करेगा।

विभिन्न विभागों में कार्यरत निगरानी व्यवस्थाओं को एकीकृत किया जाएगा, जिससे समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। आगामी समय में गुजरात शहरी विकास मिशन एक एकीकृत, डिजिटल और रियल-टाइम जानकारी देने वाला प्लेटफॉर्म विकसित करेगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य के शहरों में तालाबों और हवा की गुणवत्ता की निगरानी की जा सकेगी और चेतावनी मिलने के बाद समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। लगभग 10 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ यह पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय भूमिका निभाएगी।

कार्रवाई करना संभव हो जाएगा। इसके अलावा, राज्य की 17 की महानगर पालिकाओं और 152 नगर पालिका क्षेत्रों में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे। इन उपकरणों के माध्यम से वायु गुणवत्ता सूचकांक या एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) रियल-टाइम में हवा की गुणवत्ता की जानकारी देगा। एक्यूआई बढ़ने से अपने आप अलर्ट जनरेट होगा, जिसके आधार पर संबंधित विभाग तत्काल कदम उठा सकेगा। यह पहल शहरी स्तर के जीवन के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। शहर के तालाबों और हवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के बाद, उसकी जानकारी राज्य स्तर पर एकत्र की जाएगी। इस डैशबोर्ड में मैप, ट्रेड, अलर्ट और कार्रवाई की स्थिति के संबंध में जानकारी उपलब्ध होगी। नतीजतन, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ेगा और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। नागरिकों को भी पारदर्शी तरीके से जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे जनजागरूकता बढ़ेगी। 'लेक एंड एयर वॉच' पहल राज्य में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ शहरों के टिकाऊ विकास के लिए महत्वपूर्ण साधित होगी।

'सबको घर' के प्रधानमंत्री के लक्ष्यांक को सिद्ध करने की दिशा में गुजरात का एक महत्वपूर्ण कदम

▶▶ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के आवास विहीन परिवारों को निवास के लिए आवासीय प्लॉट देने की योजना और अधिक सरल तथा व्यापक बनेगी

जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने ग्रामीण क्षेत्रों के आवास विहीन परिवारों को निवास के उद्देश्य से आवास के लिए मुफ्त प्लॉट देने की योजना को और अधिक सरल तथा व्यापक बनाने का गरीबोमुखी निर्णय लिया है। उन्होंने राज्य के पंचायत, ग्रामीण गृह निर्माण तथा ग्रामीण विकास विभाग को दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब - (1) ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले और सामाजिक, आर्थिक तथा जाति आधारित जनगणना 2011 (एसईसीसी) में शामिल परिवार, या (2) केंद्र या राज्य सरकार की आवास योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आंबेडकर आवास योजना, पंडित दीनदयाल आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना आदि के अंतर्गत पात्रता सूची तैयार करने के उद्देश्य से किए गए किसी भी सर्वे के अंतर्गत आवास योजना की सहायता पाने के लिए योग्य हो या

पात्रता रखने वाले परिवारों की सूची में शामिल किए जाने के योग्य हों, या (3) राज्य या केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली आवास संबंधी योजनाओं की सहायता के लिए उन योजनाओं के मानकों के अनुसार पात्रता रखते हों; ऐसे लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जिनके लिए विभिन्न कल्याण योजनाएं बनाई जाती हैं, उन सभी जरूरतमंद लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ 100 प्रतिशत पहुंचाने के लिए सेचुरेशन एप्रोच अपनाने की प्रेरणा दी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के इस गरीबोमुखी निर्णय के परिणामस्वरूप आवास विहीन अधिक ग्रामीण गरीबों को आवास के लिए आवासीय प्लॉट मिल सकेगा तथा सभी जरूरतमंद लाभार्थियों को शामिल करते हुए यह सेचुरेशन एप्रोच भी साकार कर सकेगा।

औद्योगीकरण के साथ-साथ बेरोजगारी और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है: विकास मॉडल पर विचार करने की आवश्यकता है

(छानलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल औद्योगीकरण का है। कृषि प्रधान समाज का औद्योगीकरण कैसे किया जाए? इसके लिए हमारे सामने केवल एक ही आदर्श है, और वह है यूरोप के देश। जिस तरह से उन सभी देशों ने अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दियों में अपने समाज को औद्योगिक समाज में परिवर्तित किया, जिस तरह से उन्होंने अपना औद्योगिक विकास किया, उसी तरह हमें भी अपना औद्योगिक विकास करना चाहिए। इसके लिए यूरोप के देशों का आदर्श हमारे सामने आता है। और यही आदर्श मॉडल है। हम ऐसा महसूस करते हैं।

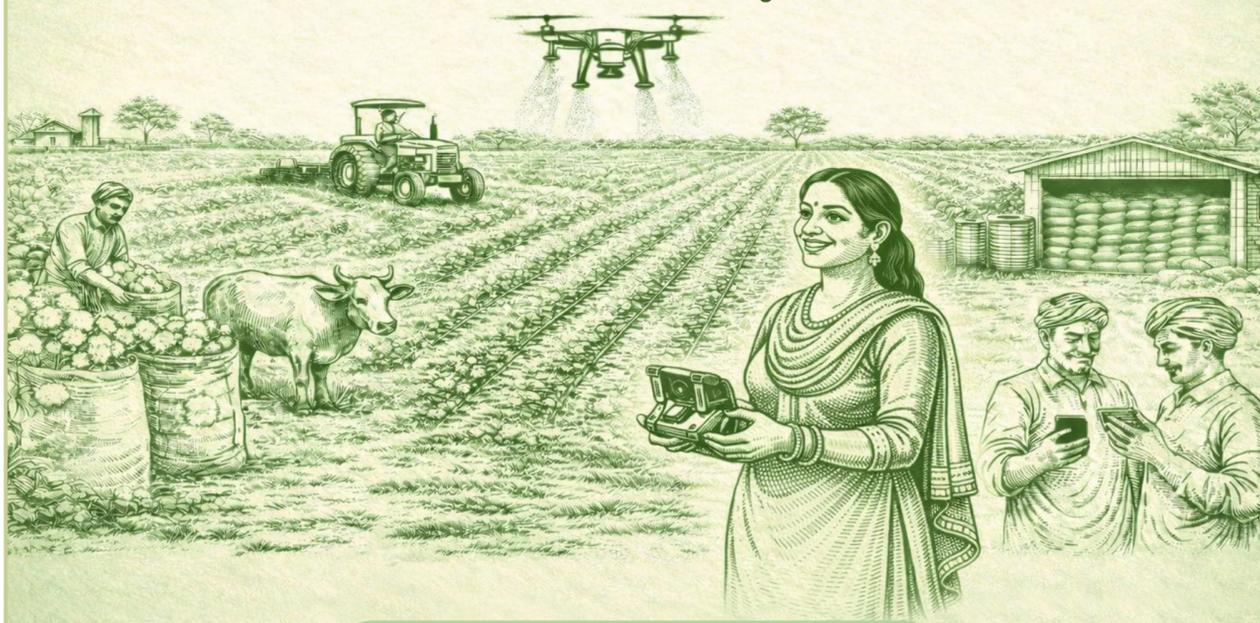
हमें सोचना चाहिए कि इसे शांतिपूर्ण ढंग से, आसानी से, समाज में कोई बड़ा उथल-पुथल मचाए बिना और किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हिंसक प्रभावों के बिना कैसे किया जा सकता है। दीर्घकाल में क्या होगा, यह कहना असंभव है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस प्रकार के औद्योगीकरण के अंतरिम काल में, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का प्रश्न अवश्य उठता है। औद्योगीकरण के कारण, लोगों के पारंपरिक चल रहे व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित होते हैं। वे व्यवसाय समाप्त हो जाते हैं और लोग बेरोजगार हो जाते हैं। नए उद्योग सभी बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। और इसलिए अनेक लोगों की बेरोजगारी का भयावह प्रश्न उठता है। इसके अलावा, आज के समय में चल रहे विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान की प्रकृति में भी बदलाव लाना होगा। आज ये अनुसंधान केवल शहरों और बड़े उद्योगों को ध्यान में रखकर ही किए जा रहे हैं।

इसके बजाय, ये अनुसंधान ऐसे होने चाहिए जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने में हमारी मदद करें। इसी प्रकार, आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में किसी अन्य चर्चा या विवाद में न पड़ें। आइए केवल व्यवहारिक पहलुओं पर विचार करें। लोकतंत्र का अर्थ है जनता की अपनी शासन प्रणाली, और वह भी समस्त जनता की। स्वाभाविक रूप से, इसका अर्थ यह है कि आर्थिक दृष्टि से यह प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे सभी लोग का विकास हो। सभी लोग समृद्ध हों। यही लोकतंत्र का वास्तविक सार है। यही इसका वास्तविक उद्देश्य है। इसलिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी कोई भी आर्थिक प्रणाली नहीं चलनी चाहिए जिससे किसी भी जनता को हानि पहुंचे। यहां तक कि औद्योगीकरण के दौरान भी, यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी को इससे हानि उठानी पड़े, तो कम से कम उसे ही हानि हो और मानवीय मूल्यों को ठेस न पहुंचे, यही लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है।



गुजरात सरकार

कृषि, किसान कल्याण और सहकार विभाग के लिए बजट में ₹24,022 करोड़ का प्रावधान



अन्नदाता का करे सत्कार, कृषि समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध गुजरात सरकार

कृषि व्यवस्था को प्राथमिकता

- किसानों को बिजली सहायता के लिए **₹9,324 करोड़** का प्रावधान
- कृषि यंत्रीकरण के अंतर्गत ट्रैक्टर खरीद सहायता के लिए **₹800 करोड़** का प्रावधान
- छोटे गोदाम बनाने हेतु मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना के अंतर्गत **₹154 करोड़** का प्रावधान

खेती में आधुनिक तकनीक के लिए प्रावधान

आधुनिक ड्रोन तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहन देने तथा सीड रिप्लेसमेंट रेट बढ़ाने के लिए **₹77 करोड़** का प्रावधान

कृषि विश्वविद्यालयों के लिए विशेष प्रावधान

कामधेनु विश्वविद्यालय में पशु विज्ञान, डेयरी विज्ञान और मत्स्य विज्ञान की विभिन्न योजनाओं के लिए **₹424 करोड़** का प्रावधान

प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन

प्राकृतिक कृषि की विभिन्न गतिविधियों के लिए **₹392 करोड़** का प्रावधान

मत्स्य उद्योग में आधारभूत सुविधाएँ

मछुआरों को डीज़ल खरीद पर वैट राहत सहायता के लिए **₹300 करोड़** का प्रावधान



"किसानों के आर्थिक उत्कर्ष और आधुनिक कृषि को केंद्र में रखकर तैयार किया गया यह बजट, हमारे अन्नदाताओं को अधिक सशक्त बनाएगा। नई तकनीक और प्राकृतिक खेती के समन्वय से हम गुजरात के कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।"

- श्री हर्ष संघवी, माननीय उपमुख्यमंत्री, गुजरात



